

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1999/अग्रहायण 24, 1921

No. 275]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1999/AGRAHAYANA 24, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1999

फा. सं. 31/11/99-बि.क. (भाग).—दिनांक 16-11-1999 को सम्पन्न सभी राज्यों/केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय बिक्री कर को युक्ति संगत बनाने के लिए इसमें और आगे तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि इसका संबंध, राज्यों का कर आधार बढ़ाने तथा सेवा कर, प्रेषण कर तथा घोषित माल के साथ जुड़ा है।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, भारत सरकार ने इस अध्ययन संबंधी कार्य को "नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी" को सौंपने का निर्णय लिया है। दि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी इस अध्ययन कार्य को अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

डा. जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th December, 1999

F. No. 31/11/99-ST (Pt.).—In the Conference of Chief Ministers and Finance Ministers of all the States/ Union Territories held on 16-11-1999, it was unanimously decided that rationalisation of Central Sales-tax needs further technical study as it is linked with widening of tax base of States and with service tax, consignment tax and declared goods.

2. In pursuance of this Resolution, the Government of India has decided to entrust this study to the National Institute of Public Finance & Policy. The National Institute of Public Finance & Policy will complete this study within two months from the date of issue of Notification and submit its report to the Government of India.

Dr. G. C. SRIVASTAVA, Addl. Secy. (Admn.)

